(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से रुग्ण उद्योगों की सहकारी समितियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिये रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के मौजूदा उपबंधों में संशोधन करके सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल के पास भेजने का निर्णय किया है । इन योजनाओं को बनाने के एक भाग के रूप में मण्डल सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को उस उद्यम के कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी समितियों को सौंपने का निर्णय कर सकता है ।

घटिया किस्म के पेंट के कारण मारुति कारों का अस्वीकार किया जाना

729. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में "मारुति एक्सपोर्ट्स स्टाल्ड बाई पुअर पेंट सप्लाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पेंट की घटिया क्वालिटी की वजह से हाल ही में निर्यात की गई अनेक मारुति कारों को अस्वीकार कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी कारें थीं तथा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण कम्पनी को कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(घ) क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो की गई इस जांच का ब्यौरा क्या है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए निर्मित 673 कारों की पेंट की क्वालिटी में दोष का चूंकि शिपमेंट से पूर्व ही पता लग गया था, अतः ये कारें निर्यात नहीं की गई । आवश्यक मरम्मत किए जाने और पेंट के मूल आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत पूरी होने के बाद ही कम्पनी को पेंट की क्वालिटी में दोष के हुए वित्तीय घाटे का पता चल सकेगा ।

(घ) और (ङ०) अन्तवर्ती पेंट की परत संतोषजनक न होने से ऊपरी परत के चिपकाव में कमी के कारण दोष उत्पन्न हो गया था । घाटे के सम्बन्ध में पेंट के आपूर्तिकर्ता से बातचीत की जायेगी

New sugar factories in Andhra Pradesh

730. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of licences proposed to be issue for new sugar factories in Andhra Pradesh during the Eighth Five Year Plan; and

(h) the number of them proposed to be set up in the Joint Sector. Private Sector and the Co-operative Sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRl P J-KURIEN): (a) and (b) The revised Guideline's for licensing of new and expansion of existing sagar factories for the Sugar Year 1991-92 and the Eighth Five Year Plan have been issued by the Government vide Press Note No. 16 dated 8th November, 1991. According to the Guidelines, while granting licences for new units and expansion projects, the additional capacity to be created upto the end of the Eighth Five Year Plan will h» kept in